



दैनिक

भारतीय बस्ती



भारतीय बस्ती आनंदन नृत्य 25रुपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं० B.S.T 59 बस्ती, वर्ष 45 अंक 161 सोमवार 1 जनवरी 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या-फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ 4मूल्य:3.00 रुपया | www.bhartiyabasti.com

नव वर्ष की मंगलकामना



नया वर्ष हमें सृजन की ओर ले चले। भारतीय बस्ती के पाठकों, विधानमंडलाओं, शुभंभू, छ्छा, को हार्दिक मंगलकामना-

- सभापदक

मुख्यमंत्री योगी, एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी



को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमका भरा ई-मेल भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को भेजा गया। देवेंद्र को भी मारने की धमकी दी गई है। ई-मेल भेजने वाले ने खुद को आईएसआई से जुड़ा बताया है। यूपी-112 के इन्स्पेक्टर की तहरीर पर सुशांत गौल्ड सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के साथ एटीएस की प्रकरण की जांच में

पुण्य तिथि पर समाजवादियों ने किया लोक बंधु राज नारायण को नमन



करते रहे। संजालन करते हुए समीर चौधरी ने राजनारायण जी के जीवन संघर्ष और उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। पुण्य तिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से जावेद सिद्दीकरी, आरविन्द सोनकर, मो. स्वाहल, नुरस आराम, मो. उमर खान, दिनेश तिवारी, जौबुलाल यादव, राम सुरेश सोनकर, फौजदार यादव, राजाराम यादव, अमर जनाल, महेश कुमार भोला पाण्डेय, गौरीशंकर यादव, छोड़ू मिश्र, रतिकान्त निषाद, अंकित कुमार पाण्डेय, उदित पाण्डेय, तुषारणी यादव, चन्द्र प्रकाश सोनी, राजू प्रसाद सोनी, नसीबुल्लाह, राजकुमार, जीत बहादुर सिंह, आनन्द चौधरी, लखवत सिंह, राममन यादव, रजनीश यादव, सलीम, विठिन तिवारी, दिनेश यादव, मो. हादर, विवेक यादव, केशव यादव, गणप पाण्डेय, रामकृष्ण यादव, विजय कुमार यादव, मुस्तफा खानकर, डा. देवेंद्रनाथ श्रीवास्तव, अमरेंद्र पाण्डेय विन्ध्य, धर्मराज यादव, रामचन्द्र, हरे श्याम विवेकानंद, सुधांवी चौधरी, अशोक कुमार बहोतान, उर्दीलाल, साहिक राम गौड़, के साथ ही साथ के अनेक पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने राजनारायण जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुगंध अर्पित किया।

नया वर्ष की मंगलकामना

नया वर्ष हमें सृजन की ओर ले चले। भारतीय बस्ती के पाठकों, विधानमंडलाओं, शुभंभू, छ्छा, को हार्दिक मंगलकामना-

निषाद पार्टी का संकल्प दिवस 13 को, कार्यकर्ता बैठक में बनी रणनीति



निषाद पार्टी का संकल्प दिवस 13 को, कार्यकर्ता बैठक में बनी रणनीति

डा. अमित निषाद का किया फूल मालाओं के साथ स्वागत



जगनाे का काम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आगामी 13 जनवरी को रामदेवी पार्क लखनऊ में पार्टी का 11 वां संकल्प दिवस आयोजित किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के विभिन्न हिस्सों से लोग एकत्र होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कोषिनेट मंत्री डा. संजय निषाद एकजुटता का संदेश देंगे। इसी संकल्प दिवस में आगामी लोकसभा की रणनीति तय की जायेगी। इस मौके

बीएचयू गैंग रेप मामले में भाजपा से जुड़े तीन गिरफ्तार



बीएचयू गैंग रेप मामले में भाजपा से जुड़े तीन गिरफ्तार

कांग्रेस नेता महेन्द्र ने किया अलाव जलवाने, कम्बल वितरण की मांग



कांग्रेस नेता महेन्द्र ने किया अलाव जलवाने, कम्बल वितरण की मांग

नव वर्ष की मंगलकामना



बाला जी ट्रेडर्स सोनहा बाजार-बस्ती, हेड ऑफिस पाण्डेय बाजार खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं के विक्रेता

प्रो. शशांक अग्रवाल मो 9919803021

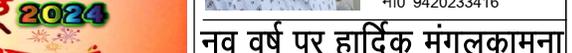
कसौधन टेटर्स सोनहा बाजार बस्ती

खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं के विक्रेता प्रो. प्रेमचन्द्र गुप्त मो 9935263071, 9792096494

आलोक अम्बेडकर बौद्ध बिहार ग्राम नरखोरिया पोस्ट- असनहरा जनपद बस्ती

प्रबन्धक फूलचन्द्र मो 9919234226

नव वर्ष पर नगर पंचायत भानपुरवासियों को हार्दिक शुभकामना



चन्द्रभान यादव भावी समासद प्रत्याशी नगर पंचायत भानपुर वार्ड नं. 9 कृष्णानगर ग्राम- आमा पोस्ट- सोनहा जनपद बस्ती मो 9420233416

नव वर्ष पर हार्दिक मंगलकामना



श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी शिवपूजन ग्राम प्रधान- परसा लंगड़ा विकास खण्ड- सल्टीआ गोपालपुर जनपद- बस्ती मो 9839260632

नव वर्ष पर हार्दिक मंगलकामना



रामनेवास यादव उर्फ रामलौट ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत- तेनुआ विकास खण्ड- सल्टीआ गोपालपुर जनपद- बस्ती मो 9918425402

HAPPY NEW YEAR 2024

आप सभी देशवासियों को नया साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रभारी निरीक्षक सोनहा विनोद कुमार मिश्रा जलपद - बस्ती उ० प्र० मो 9454403223

पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी जनपद - बस्ती उ० प्र०

HAPPY NEW YEAR 2024

आप सभी देशवासियों को नया साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं

सियाराम गुप्ता (समाजसेवी) ग्राम आमा पो० सोनहा जिला बस्ती उ० प्र० मो : 8874541936

HAPPY NEW YEAR 2024

आप सभी देशवासियों को नया साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं

राम प्रसाद चौधरी पूर्व कैबिनेट मंत्री

HAPPY NEW YEAR 2024

आप सभी देशवासियों को नया साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रेमनाथ निषाद (समाजसेवी) ग्राम आमा, पो० - सोनहा जिला बस्ती उ० प्र० मो : 9400068807

आप सभी को नववर्ष, मकर-संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

विष्णु दात शुक्ल (मिलाज्वला) 30 प्र जूनियर हार्डस्कूल शिक्षक संघ-बस्ती

आप सभी को नववर्ष, मकर-संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

श्याम सुन्दर (प्रधान प्रतिनिधि) ग्राम सभा-मिर्कोश कसा, विकासखण्ड बनकटी-बस्ती

आप सभी को नववर्ष, मकर-संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अमरेश चन्द्र (प्रधान) ग्राम सभा-सिसवा पाण्डेय, विकासखण्ड बनकटी-बस्ती

आप सभी को नववर्ष, मकर-संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

अमरेश चन्द्र (प्रधान) ग्राम सभा-सिसवा पाण्डेय, विकासखण्ड बनकटी-बस्ती

"युद्ध अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता" -वेदेल फिलिप

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 1 जनवरी 2024 सोमवार

सम्पादकीय

नये वर्ष से जगी आशा

हर नया वर्ष यह उम्मीद जगता है कि जो पहले नहीं हुआ इस वर्ष हो जायेगा। 2023 के आगमन के समय भी वही आशा, उमंग थी जैसा 2024 के लिये है। सब कुछ अच्छा ही होगा ऐसा कहाँ हो पाता है। फिर भी हमें अपनी आशा को कर्तव्य पथ के साथ जीवन्त रखना होगा। कोई भी वर्ष 2023 को रेखांकित करने वाली दुखद घटनाओं की भयावह कहानी पर अफसोसजनक वृष्टि डाल सकता है। यूक्रेन पर अनावश्यक रूसी आक्रमण निरंतर जारी है। इसी तरह वास्तविक नियंत्रण रेखा (एफ.ए.सी.) के पार भारतीय क्षेत्र में चीनी अतिप्रभुता 3000 महीने में प्रवेश कर गया। भारत में भी वही की शुरुआत प्रैक की बची-खुची स्वतंत्रता पर सीधे हमले के साथ हुई, जब केंद्र सरकार ने बी.बी.सी. की दो-भाषी वाली डॉक्ट्रिन को फॉरिस्ट्रियन करार देकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया।

मार्च की शुरुआत में सुप्रिम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैंसला फैसला कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। इस फैसले की पूर्ण अवहेलना करते हुए, सरकार ने संसद में एक विधेयक पारित किया जो मुख्य न्यायाधीश की जगह एक मंत्री को नियुक्त करता है, जिससे मुख्य को चुनाव अधिनियम में आधिकारियों की नियुक्ति करने में छूट मिल जाती है, और देश में चुनावी आधिपत्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है।

मार्च में, मणिपुर राज्य में मैटैई/अई कुकी जनजातीय समुदायों के बीच भीषण जातीय हिंसा भड़क उठी। भाजपा शासित राज्य होने के बावजूद सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत राज्य से सूचना के प्रवाह को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। विपक्ष द्वारा मणिपुर की जमीनी स्थिति स्पष्ट करने के आग्रह के बाद भी प्रधानमंत्री ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। अब भी, जमीनी तथ्य अस्पष्टता में डूबे हुए हैं और सर्वोच्च न्यायालय को असहज शांति की ओर धीमी गति से आगे बढ़ने की निगरानी करनी पड़ रही है।

स्वतंत्र भारत की मुद्रा व्यवस्था के इतिहास में किसी भी मूल्यवर्ग की शौक लाइफ 2000 रूपए के नोट से कम नहीं रही है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 2016 में सरकार की नई धरोहर की नीति किंतनी कठोर और अदृशदर्शी थी और कैसे एक 'डार्क कॉमिडी' के सभी रंगों के साथ उस दुखद निर्णय से कुछ भी नहीं सीखा गया। सितम्बर में संसद को अपने ऐतिहासिक स्थल को छोड़कर एक नए परिसर में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया गया था। मूल संसद भवन को एक पुरानी सभ्यता को आधुनिक राष्ट्र में बदलने में पिछले 7 दशकों में निर्माई गई मौलिक भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए 'संविधान सभा' में बदल दिया गया था। इस बदलाव के कारण अमी भी अस्पष्ट हैं क्योंकि पुरानी संरचना अमी भी जीवन्तता, रहस्य और वेदांग गरिमा की आभा विखेती हुई खड़ी है।

अनुसूचकों में भयावह आंदोलनियों हमले को देखा, जिसमें असहाय इसराईली नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें सैंकड़ों लोग मार गए और अनजानत घायल हुए। इसराईली जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी की अनुप्राणहीन आबादी को सामूहिक दंड के सबसे म्थे यकालीन रूप का सामना करना पड़ा, जो अमी भी बच्चों और महिलाओं के साथ बद्रस्त्रु जारी है। नवम्बर में 8 वंशानुगत नौसैना कर्मियों को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई। हालांकि सजा-ए-मौत को कैद में बदल दिया गया है। मने इस युद्ध को दिसम्बर 2022 में संसद में उठाया था, जिसके कई महीने बाद भी हमारे 'सुयोगित दिग्गजों' को उनके सिर पर मौत की सजा के साथ अपमानजनक जेल की सजा मुहानटी पड़ रही है।

दिसम्बर की शुरुआत में अनुच्छेद 370 पर फंसले की घोषणा हुई। हमारे देश के संघीय ढांचे पर इसके हानिकारक प्रभाव से हम सभी को क्षिपित होना चाहिये। अदालत ने इस सवाल का जवाब देने से परहेज किया कि क्या संसद एक राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल सकती है जो विवाद का अनिवार्य कारण था। शीर्ष अदालत ने इस आकांक्षी प्रश्न को केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने की भी अनुमति दी कि सोलिसिटर जनरल ने वायदा किया है कि जम्मू और कश्मीर के शेष हिस्से में राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। ऐसा उपक्रम जो उस मामले में किसी उत्तराधिकारी सरकार या क्तिप्रािका पर बाधकारी नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से न्यायालय ने माना कि जहां अनुच्छेद-370 को निरस्त करने की प्रक्रिया भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी, वहीं इस निरस्त करना स्वयं अधिकार क्षेत्र के बाहर था।

साल का अंत अखिरकार भारत के लोकतंत्र पर शाब्दिक हमले के 22वीं वर्षीय। 13 दिसम्बर, 2023 को - संसद पर आतंकी हमले की सजा करती पर 2 घुसपैठियों को निरस्त करने में प्रवेश किया और घुसां छोड़ा। इसके विपरीत, खुद को किसी और शासनदी के बजाए और किसी भी सर्वाधिकारि जाच से खुद को बरी करने से लिए, सरकार ने 146 विधायी संसद सदस्यों को निर्दोषित कर दिया, जिससे भारत की संसदीय सरकार के लिए एक भयावक मिसाल कायम हुई। इन स्थानों में बीच, दूरस्थभार विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और 3 आरपाधिक कानून विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक शून्य के साथ पारित किए गए।

2023 को रेखांकित करने वाली मौलिक घटनाओं की शृंखला में 'मॉन्ट्रि' की प्रतिबन्धित भाषाई शब्दावली से परे फैली हुई है। यह उस वर्ष के लिए एक रूपक बन जाता है जहां वास्तविकता और भ्रम के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जिससे नागरिक स्वच्छाई के विवृत्त संस्करणों से संजुग रहते हैं। दक्षिणपंथी लोकतन्त्रमानववाद, वैश्वीकरण विहादों और संविधान का पालन न करने की ओर, वैश्वीकरण युवाक शासन के एक परेशान करने वाले पैटर्न को रेखांकित करता है जो पारदर्शिता पर नियंत्रण और जवाबदेही पर शक्ति को प्राथमिकता देता है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि 2024 किंतना सार्थक होगा।

वर्ष 2024 से जगी उम्मीदें

—प्रहलाद सबानी—

विश्व के कुछ देश वर्ष 2024 में मंदी की मार झेल सकते हैं, यह कुछ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का आकलन है। परंतु, वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था के गिरने की सम्भावनाओं के बीच एक देश ऐसा भी है, जिस पर समस्त अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक, की नजर टिकी है, वह है भारत। भारत विश्व अर्थव्यवस्था के प्रति समस्त विदेशी वित्तीय संस्थान आशावात हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब लागत ही सहारा देने की क्षमता रखता है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अभी हाल ही में एक प्रतिवेदन जारी किया है। इसमें भारत के प्रति मुख्य रूप से तीन बातें कही गई हैं। प्रथम, भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। दूसरे, भारत का सकल घरेलू उत्पाद 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करेगा। तीसरे, वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में भारत का योगदान 16 प्रतिशत का रहने वाला है। भारत आने वाले समय में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में एक वृद्धि के रूप में अपना योगदान देने को तैयार है। भारत ने वर्ष 2023 में विश्व में कम होती विकास दर के बीच भी अर्थव्यवस्था विकसित कर हासिल की है। क्योंकि, भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में, विश्व रूप से आर्थिक क्षेत्र में, लगातार कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनका प्रभाव अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से दिखाई



देने लगा है। एक तो भारत ने आर्थिक व्यवहारों का डिजिटलाकरण किया है और इस क्षेत्र में पूरे विश्व को ही राह दिखाई है, इससे आर्थिक व्यवहारों की न केवल नियुगता बढ़ी है बल्कि लागत भी बहुत कम हुई है। दूसरे, केंद्र सरकार ने देश में आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए भारी भरकम राशि का पूंजीगत खर्च किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.50 लाख करोड़ रुपए की राशि इस मद्द पर खर्च की गई थी और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10 लाख करोड़ रुपए की राशि इस मद्द पर खर्च की जा रही है। भारत में सड़क, रेलवे एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर 12,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर

का पूंजीगत खर्च आगे आने वाले समय में किये जाने की योजना बनाई गई है। वर्ष 2017 से 2023 के बीच आधारभूत संरचना के विकास हेतु 70 लाख करोड़ रुपए की राशि का पूंजीगत खर्च किया गया था परंतु वर्ष 2024 से 2030 के बीच 143 लाख करोड़ रुपए की राशि का पूंजीगत खर्च किए जाने की योजना बनाई जा रही है। तीसरे, भारत में केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को कई योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने की भरपूर कोशिश की है, जिसका परिणाम इस वर्ग की संख्या में भारी भरकम कमी के रूप में देखने को मिला है।

और फिर, अब तो यह वर्ग मध्य वर्ग की श्रेणी में शामिल होकर भारत में उत्पादों की मांग में वृद्धि करने में सहायक की भूमिका निभा रहा है, जिससे देश में ही विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में भारी वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार, विश्व के सबसे बड़े ऑफिस कामप्लेक्स का निर्माण भारत में गुजरात राज्य के सूरात शहर में किया गया है। तीसरे, भारत में 4,500 से अधिक हीरा व्यावसायिकों के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। इस कामप्लेक्स में कच्चे हीरों के व्यापारियों से लेकर पॉलिश हीरों की विक्री करने वाले कम्पनियों के ऑफिस एक ही जगह पर स्थापित किए जाएंगे। सूरात डायमंड बोर्स

बिल्डिंग के नाम से इस कामप्लेक्स के क्षेत्र में फैला है, का उद्घाटन दिसम्बर 2024 माह में भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सम्यन् हुआ है। यह कामप्लेक्स अमेरिका के रेखा विभागे पेंटागन के मुख्यालय बनने से भी बड़ा है, पेंटागन के मुख्यालय को आज तक विश्व में सबसे बड़ा भवन माना जाता रहा है। इस तरह के कई व्यावसायिक क्षेत्र भारत में विकसित हो रहे हैं।

विश्व के अन्य देश मुद्रा स्फीति की समस्या से पिछले कुछ वर्षों से लगातार जूझते रहे हैं परंतु भारत पर इस समस्या पर ही नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। जुलाई 2023 में भारत में खुदरा महंगाई दर 7.44 प्रतिशत थी जो अक्टूबर 2023 में घटकर 4.87 प्रतिशत पर लीने आ गई है। अब तो शीघ्र ही भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर में कमी की घोषणा कर सकता है जिससे देश में व्याज की दरें कम होना शुरू होगी इससे निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में और अधिक तेजी की सम्भावना होगी।

आगे आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को यदि किसी परेशानी का सामना करना पड़ता तो अंको पर बंध आंतरिक समस्या न होकर वैश्विक स्तर की समस्या से कारण होगी। क्योंकि, कुछ देशों, विकसित देशों सहित में मंदी की सम्भावनाएं बन रही हैं। दूसरे, रूस यूक्रेन युद्ध, हमलाइ इजराइल युद्ध, चीन का अपने पड़ोसी देशों से टेशन, यूरोपीयन देशों के आपसी झगडे, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो भारत की विकास दर को

बढते महिला अपराध

—योगेश कुमार गोयल—

एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो) की नवीनतम रिपोर्टों के एक बार फिर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की विज्ञानिक तस्वीर उभरकर सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के विरुद्ध अपराधिक घटनाओं के 4,45,256 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 में यह आंकड़ा 4,28,278 और 2020 में 3,71,503 था। महिलाओं के विरुद्ध अपराधिक घटनाओं के ये मामले 2021 की तुलना में करीब चार प्रतिशत ज्यादा हैं। आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार महिला सशक्तिकरण का किंतनी भी दायर करे, वास्तविकता यही है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में मामलों में कोई सुधार नहीं आया है। उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा बढ़े हैं, जबकि दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर सर्वाधिक बताई गई है। दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तराखण्ड में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में मामलों में सर्वाधिक प्राथमिकी दर्ज हुई।



दिल्ली और राजस्थान जहां महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य हैं, वहीं दहेज के लिए जान लेने वालों में पहले स्थान पर उत्तरप्रदेश और दूसरे पर बिहार हैं। उत्तरप्रदेश में 2138 और बिहार में 1057 महिलाओं की हत्या कर दी गई, जबकि मध्यप्रदेश में 518, राजस्थान में 451 और दिल्ली में 131 महिलाओं की हत्या दहेज के लिए की गई। 'एनसीआरबी' के अनुसार प्रति एक लाख जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 2021 में 64.5 फीसद से बढ़कर 2022 में 66 फीसद हो गई, जिसमें से 2022 के दौरान 19 महानगरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 48,755 मामले दर्ज किए गए। 2021 के 43,414 मामलों की तुलना में 12.3 फीसद ज्यादा हैं।

बलात्कार और सहजीवन में जान गंवाने के मामले में स्थिति काफी दयनीय है। यह किंतनी बड़ी विडम्बना है कि महिलाएं न परिवार में, न आस-पड़ोस में खुद को ही बाहर के वातावरण में और जो पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े देखें तो 2023 के 19 सितंबर तक ही महिलाओं के खिलाफ अपराध की कुल 20,693 शिकायतें मिलीं, जिनके इस वर्ष के अंत तक बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2022 में आयोग को 30,987 शिकायतें मिली थीं, जो 2014 के बाद उन्नीसवीं, वर्ष 2014 में 30,906 और 2021 में 30 हजार से ज्यादा अपराधों की 30 हजार से ज्यादा शिकायतें मिली थीं। आयोग ने तेजाब हमले, महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध, दहेज हत्या, बॉय शापण और दुर्घटना जैसी कुल 24 श्रेणियों में विकसित की हैं। सर्वाधिक शिकायतें गैरिना के साथ जीने के अधिकार को लेकर दर्ज की गईं, उससे बाद परतू हिंसा, दहेज उन्नीसवीं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, छेड़छाड़ और बलात्कार की शिकायतें हैं। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद महिलाओं के प्रति अपराधों पर लगातार करने के लिए जिस प्रकार कानून सख्त किया गया, उससे लगा था कि समाज में

जनसंख्या का बढ़ता दबाव



—मनु गौड़—

यह याद रखा जाएगा कि भारत साल 2023 में सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया। भारत क्या अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएगा? भारत की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए अनेक सांठगणों द्वारा एक दशक से जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई प्रयास किए गए। साथ ही, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने हेतु तीव्र आवाज भी उठाने दे लनी। ध्यान रहे, 1970 के दशक में जब भारत द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर नरबन्दी कार्यक्रम चलाए गए, उसी 1970 के दशक में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए चीन द्वारा भी 35 वर्ष के लिए एक संतान की नीति अपनाई गई। दुनिया की लगभग 37 प्रतिशत जनसंख्या इन्हीं दोनों देशों में निवास करती है।

जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में भारत और चीन के बढ़ते कदम को देखते हुए वैश्विक स्तर पर परिष्कृत सुसज्ज राष्ट्रों के सांठगण भी सक्रिय हो गए थे। विभिन्न देशों द्वारा चलाई जा रही जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित नीतियों पर अंशु लागू करने के उद्देश्य से अनेक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने लगे थे। इन देशों का मसदार बड़ी आबादी वाले राष्ट्रों को एक बाजार के रूप में देवना तथा परिष्कृत महाद्वीप में शरीबी व अस्थिराण पराज्य रचना भी था, जिससे ये राष्ट्र अपनी बड़ी जनसंख्या वाले संसाधनों की कमी से सहज जुझ रहे और कभी भी विकसित देश की श्रेणी में न आ सके। ऐसे सम्मेलनों में साल 1994 में आयोजित इंटरनेशनल कांफे्रेंस फॉर पॉपुलेशन एंड डेवेलपमेंट (आईसीपीडी) प्रमुख है। चीन ने इस बाल को समर रहते समर लिया और यही कारण है कि वह आज विकसित राष्ट्र की श्रेणी में अपना स्थान बना चुका है। दूसरी ओर, भारत अमी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को विलुप्त सुविधाएं उपलब्ध करने की कोशिशें इतक रहा है। अगर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि इतने बड़ी आबादी के बावजूद हम प्रगति कर रहे हैं।

जिस प्रकार मौजूदा सत्तारूढ़ ने अनुच्छेद-370 को हटाया था तीन तलकों को समाप्त किया है या देश में विपरीत रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यदि इन्हीं समस्त कारणों से कुछ विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं तो भारत से विभिन्न उत्पादों का निर्यात भी कम होगा, आयात होने वाली वस्तुओं की लागत बढ़ेगी, इस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं जो भारत को भी आने वाले समय में परेशान करें। दूसरे, कुछ प्राकृतिक कारण भी जैसे मानसून का उचित समय पर नहीं आना अथवा कम बारिश होना, जैसी कुछ समस्याएं भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। अन्वया पिछले लगभग 10 वर्ष का समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए स्वर्णिम काल का समय चाहिए और आगे आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था नई उचाईयों को छूने के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए यह इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि भारतीय शेर बाजार बाजार वर्ष 2016 से लेकर वर्ष 2023 तक लगातार 8 वर्षों तक निवेशकों को लाभ की स्थिति प्रदान करता रहा है। दूसरे, अमेरिकी वित्तीय संस्था लीहमन ब्रदर्स के वर्ष 2008 में टूटने के बाद भारत का निर्यात एक चीन का शार्पाई शेर बाजार 3000 के अंको पर थे परंतु आज भारत का निर्यात 21800 अंको के ऊपर पहुंच गया है और चीन का शार्पाई शेर बाजार अमी भी 3000 अंको पर ही बरकरार है। लगभग समस्त देशों के प्रति अर्थव्यवस्था परेशान होकर है और आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 60,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है।

हमें सम्मरण होना, बुजुर्गों की अधिक संख्या संबंधी कम फैलाने की मुक्त संकल्प मजबूत करने है कि भारत जनसंख्या नियंत्रण की नीति न बनाए और संरक्षकों की कमी के कारण गरीबों, बेरोजगारों, मुकम्मरी, प्रदूषण आदि की समस्याएं नहीं बढ़ें। यदि भारत की वास्तव में विश्व में विश्वविद्यालयी राष्ट्र के रूप में उभरना है, तो नए साल में किसी परिष्कृत देशों के लिए प्रयास करना चाहिए, जहां 15 अगस्त, 2019 को लाल फिले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था। (य लेखक को अपने विचार हैं)

